

## Weekly One Liners 04<sup>th</sup> to 10<sup>th</sup> May, 2026

### वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 रिपोर्ट में ग्लोबल प्रेस फ्रीडम रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंची

लेटेस्ट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में 180 देशों में भारत 157वें नंबर पर है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की लेटेस्ट सालाना रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया भर में प्रेस की आज़ादी दशकों में अपने सबसे कमज़ोर पॉइंट पर पहुँच गई है। ग्रुप का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जो 180 देशों को इवैल्यूएट करता है, ने इंडेक्स के 25 साल के इतिहास में अपना सबसे कम एवरेज स्कोर रिकॉर्ड किया है। पहली बार, इवैल्यूएट किए गए आधे से ज़्यादा देश 'मुश्किल' या 'बहुत गंभीर' कैटेगरी में आते हैं।

### विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को समझना

वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इन पांच खास इंडिकेटर्स के आधार पर सभी देशों का मूल्यांकन करता है।

1. राजनीतिक वातावरण
2. कानूनी ढांचा
3. आर्थिक स्थितियाँ
4. सामाजिक संदर्भ
5. पत्रकारों की सुरक्षा

यह हर देश में पत्रकारिता कितनी आज़ाद और सुरक्षित है, इसकी पूरी तस्वीर दिखाता है।

सबसे अच्छी प्रेस आज़ादी वाले टॉप 10 देश

इस साल एक बार फिर यूरोपियन देशों ने लिस्ट में अपना दबदबा बनाया है और वे अपने मज़बूत संस्थानों और मीडिया प्रोटेक्शन के लिए जाने जाते हैं।

### शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ देश (2026)

1. नॉर्वे
2. नीदरलैंड
3. एस्तोनिया
4. डेनमार्क
5. स्वीडन
6. फिनलैंड
7. आयरलैंड
8. स्विट्ज़रलैंड
9. लक्समबर्ग
10. पुर्तगाल

नॉर्वे लगातार 10वें साल टॉप पर बना हुआ है, जो प्रेस की आज़ादी और पत्रकार की सुरक्षा के लिए उसके मज़बूत कमिटमेंट को दिखाता है।

सबसे खराब प्रेस स्वतंत्रता वाले टॉप 10 देश

### शीर्ष 10 सबसे खराब देश (2026)

- अज़रबैजान (171)
- रूस (172)
- तुर्कमेनिस्तान (173)
- वियतनाम (174)
- अफ़गानिस्तान (175)
- सऊदी अरब (176)

- ईरान (177)
- चीन (178)
- उत्तर कोरिया (179)
- इरिट्रिया (180)

लगातार तीसरे साल इरिट्रिया मीडिया पर कड़ी पाबंदियों के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश बना हुआ है।

### संकट के बीच भारत की रैंक गिरी

रिपोर्ट के अनुसार, भारत की स्थिति पिछले एक दशक में लगातार गिरावट दिखाती है। साल 2014 में भारत 140वें स्थान पर था और हाल के सालों में इसमें थोड़ा उतार-चढ़ाव आया है और यह ट्रेंड प्रेस की आज़ादी की स्थिति में लगातार गिरावट दिखाता है।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत उन 110 से ज़्यादा देशों में से है जहाँ मीडिया को कंट्रोल करने वाला कानूनी ढांचा कमज़ोर था और पत्रकारों की बिना किसी डर या कानूनी नतीजे के आज़ादी से रिपोर्ट करने की क्षमता को लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं।

भारत और उसके पड़ोसी देशों की तुलना

भारत अब पड़ोसी देशों से नीचे रैंक पर है।

- नेपाल (87)
- मालदीव (108)
- श्रीलंका (134)
- भूटान (150)
- बांग्लादेश (152)
- पाकिस्तान (153)

'पत्रकारिता का अपराधीकरण' 2026 के लिए मुख्य चिंता

क्रिमिनलाइज़ेशन ' जैसे शब्दों का बढ़ना। इसका मतलब है पत्रकारिता के काम पर रोक लगाने या सज़ा देने के लिए कानूनों का बढ़ता इस्तेमाल।

पहचाने गए प्रमुख मुद्दे

- राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों का गलत इस्तेमाल।
- साथ ही, इमरजेंसी नियमों का इस्तेमाल और कानूनी तरीकों को लागू करके उन्हें सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित किया जाना चाहिए।
- इसके अलावा, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट पर लीगल हैरेसमेंट और दबाव जैसी चुनौतियाँ भी बढ़ रही हैं।

ग्लोबल प्रेस फ्रीडम 25 साल के सबसे निचले स्तर पर

2026 के इंडेक्स से दुनिया भर में चिंता की तस्वीर भी सामने आई है, क्योंकि प्रेस की आज़ादी 2001 के बाद सबसे निचले लेवल पर पहुंच गई है।

प्रमुख वैश्विक रुझान

- 50% से ज़्यादा देश 'मुश्किल' या 'बहुत गंभीर' कैटेगरी में आते हैं।
- इसके अलावा, 60% से ज़्यादा देशों में प्रेस की आज़ादी के कानूनी इंडिकेटर में गिरावट आई है।
- और 80% देशों में पत्रकारों के लिए सुरक्षा के तरीके कमज़ोर या बेअसर होते जा रहे हैं।

इससे पता चलता है कि यह संकट सिर्फ़ कुछ इलाकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया में फैला हुआ है।



**LIVE CLASSES**

# Online **LIVE** Classes for **SSC, Banking, Railways** and Other Govt Exams



Live & Recorded  
Classes



PDF Notes &  
Study Material



Mock Tests &  
Practice Questions



Doubt Solving  
Sessions

- ✓ **Expert Faculty** with Interactive Classes
- ✓ **Full Exam Syllabus Coverage** + Mock Tests
- ✓ **Courses Available** in Hindi, English & Regional Languages

**Get Started Now**

**भारत और वियतनाम ने संबंधों को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया**

वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और वियतनाम के सोशलिस्ट रिपब्लिक के प्रेसिडेंट, महामहिम श्री टो लैम, भारत के माननीय प्रधानमंत्री के बुलावे पर भारत आए हैं। इस दौरान ने उनके आपसी रिश्तों को एक बेहतर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा के साथ अगले लेवल पर पहुंचा दिया है और इस दौरान के नतीजे में कुल 13 मेमोरेण्डम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ( MoUs ) पर साइन हुए और कई घोषणाएं हुईं।

बढ़ी हुई व्यापक रणनीतिक साझेदारी: इसका क्या मतलब है भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय संबंधों को एक बेहतर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदलना एक महत्वपूर्ण डिप्लोमैटिक मील का पत्थर है। इस फ्रेमवर्क का मकसद स्ट्रेटेजिक सेक्टर में सहयोग को मजबूत करना है, जिसमें डिफेंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक ग्रोथ, मैरीटाइम सिक्योरिटी और लोगों के बीच कनेक्शन शामिल हैं।

साथ ही, इंडो-पैसिफिक ओशनस इनिशिएटिव (IPOI) में शामिल होने का वियतनाम का फैसला बढ़ते क्षेत्रीय सहयोग को दिखाता है। IPOI को भारत ने लॉन्च किया है जो इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, टिकाऊ समुद्री संसाधनों और क्षेत्रीय स्थिरता पर फोकस करता है।

यह मजबूत पार्टनरशिप ऐसे समय में हुई है जब दोनों देश सप्लाई चेन पर ध्यान दे रहे हैं और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने और रीजनल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर ध्यान दे रहे हैं।

**भारत और वियतनाम के बीच हुए प्रमुख समझौते**

डिजिटल भुगतान और वित्तीय नवाचार को बढ़ावा इस दौरान के दौरान सबसे ज़रूरी एग्रीमेंट में से एक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) और स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम (SBV) के बीच हुआ। यह एग्रीमेंट फाइनेंशियल इनोवेशन और डिजिटल पेमेंट स्टेटस में ऑपरेशन पर फोकस करता है।

इसके अलावा, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ वियतनाम (NAPAS) के बीच एग्रीमेंट से क्रॉस-बॉर्डर QR कोड बेस्ड इंटरऑपरेबिलिटी बनाने में भी मदद मिलेगी।

दुर्लभ पृथ्वी और प्रौद्योगिकी सहयोग का विस्तार भारत और वियतनाम ने IREL (इंडिया) लिमिटेड और वियतनाम के इस्टीमेटेड फॉर टेक्नोलॉजी ऑफ रेडियोएक्टिव एंड रेयर एलिमेंट्स (ITRRE) के बीच रेयर अर्थ एलिमेंट्स में सहयोग पर एक महत्वपूर्ण एग्रीमेंट पर भी साइन किए।

रेयर अर्थ एलिमेंट्स (REEs) इलेक्ट्रिक गाड़ियों, सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी इन्फ्रामेंट और डिफेंस टेक्नोलॉजी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। साथ ही, यह एग्रीमेंट स्ट्रेटेजिक रूप से भी ज़रूरी है क्योंकि यह कंसन्ट्रेड ग्लोबल सप्लाई चेन के विकल्प तलाशता है।

डिजिटल टेक्नोलॉजी और IT सेक्टर में अपने सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय और वियतनाम के साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्रालय के बीच एक और बड़ा एग्रीमेंट साइन किया गया।

स्वास्थ्य सेवा और दवा विनियमन सहयोग इसके अलावा, भारत और वियतनाम ने मेडिकल प्रोडक्ट्स रेगुलेशन के सेक्टर में सहयोग को बेहतर बनाने के लिए भारत के सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (CDSCO) और वियतनाम के ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बीच एक एग्रीमेंट पर साइन किए।

इस एग्रीमेंट में फार्मास्यूटिकल्स, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स और मेडिकल डिवाइस शामिल होंगे। इससे दोनों देशों के बीच हेल्थकेयर ट्रेड और रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन को आसान बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। क्योंकि भारत दुनिया भर में एक बड़े फार्मास्यूटिकल मैनुफैक्चरिंग हब के तौर पर जाना जाता है और यह पार्टनरशिप हेल्थकेयर एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट के लिए नए मौके पैदा करेगी।

**पर्यटन, संस्कृति और शिक्षा संबंध मजबूत हुए**

कई एग्रीमेंट कल्चरल और एजुकेशनल सहयोग पर फोकस थे। कल्चरल एक्टिविटीज़, एक्सचेंज और आर्टिस्टिक कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए 2026-2030 के समय के लिए एक नए कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम पर साइन किए गए।

भारत ने टूरिज्म कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर भी साइन किए हैं, जिनका मकसद ट्रेवल और लोगों के बीच बातचीत को बढ़ावा देना है।

टूरिज्म कोऑपरेशन से दोनों देशों के बीच कल्चरल जान-पहचान और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने की भी उम्मीद है।

नालंदा यूनिवर्सिटी और हो ची मिन्ह नेशनल एकेडमी ऑफ पॉलिटिक्स के बीच यह एग्रीमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग इनिशिएटिव पर फोकस करेगा।

मुंबई और हो ची मिन्ह सिटी मिलकर काम करेंगे वृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) और हो ची मिन्ह सिटी पीपुल्स कमेटी के बीच एक एग्रीमेंट का मकसद शहरी गवर्नेंस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कोऑपरेशन को बेहतर बनाना है।

इस पार्टनरशिप से दोनों मेगासिटीज़ को मदद मिलेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, स्मार्ट सिटी प्लानिंग और सस्टेनेबल अर्बन ग्रोथ के एरिया में एक्सपर्टिज़ एक्सचेंज होगी।

चाम पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण परियोजना इसके अलावा, वियतनाम में रखी भारतीय मूल की चाम मैनुस्क्रिप्ट्स के डिजिटलाइजेशन और बचाव के लिए एक कल्चरल रूप से महत्वपूर्ण एग्रीमेंट पर साइन किए गए।

इस प्रोजेक्ट में इन पुरानी मैनुस्क्रिप्ट्स का सर्वे, डॉक्यूमेंटेशन, कंज़र्वेशन और ऑनलाइन डिसेमिनेशन शामिल होगा और इससे भारत और वियतनाम के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध मजबूत होंगे।

व्यापार लक्ष्य बढ़ाकर 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर किया गया भारत और वियतनाम ने 2030 तक USD 25 बिलियन के नए द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य की घोषणा की है। दोनों देश इन क्षेत्रों में अपने सहयोग को बढ़ाना चाहते हैं,

- इलेक्ट्रॉनिक्स और अर्धचालक
- कृषि और खाद्य निर्यात
- दवाइयों
- नवीकरणीय ऊर्जा
- डिजिटल अर्थव्यवस्था
- समुद्री व्यापार

खेती-बाड़ी के व्यापार को बेहतर बनाने के लिए भारत ने वियतनाम को भारतीय अंगूर एक्सपोर्ट करने की घोषणा की है, जबकि वियतनाम भारत को ज्यूरियन एक्सपोर्ट करेगा।

भारत-वियतनाम साझेदारी क्यों मायने रखती है भारत और वियतनाम के बीच लंबे समय से सभ्यता, राजनीतिक और आर्थिक संबंध हैं जो पिछले दशक में काफी मजबूत हुए हैं।

क्योंकि दोनों देश एक-दूसरे को रीजनल स्टेबिलिटी बनाए रखने, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने और एक फ्री और ओपन इंडो-पैसिफिक पक्का करने के लिए ज़रूरी पार्टनर मानते हैं।

नेताओं ने यह भी कहा कि 2026 में भारत-वियतनाम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 10वीं सालगिरह है और वे स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस और टोस सहयोग के साझा विज्ञान के तहत अलग-अलग सेक्टर में सहयोग को गहरा करने पर सहमत हुए।

## राष्ट्रीय समाचार

- अंडमान और निकोबार आइलैंड्स ने 3 मई, 2026 को स्वराज द्वीप (हैवलॉक आइलैंड) के राधानगर बीच पर दुनिया का सबसे बड़ा पानी के नीचे का राष्ट्रीय ध्वज फहराकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 60 x 40 मीटर के इस विशाल भारतीय तिरंगे को 200 से ज़्यादा ट्रेड गोताखोरों की मदद से पानी के नीचे सफलतापूर्वक फहराया गया। इसमें मुख्य हिस्सा लेने वालों में इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, अंडमान और निकोबार पुलिस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और प्रोफेशनल स्कूबा डाइवर शामिल थे। युवा गोताखोर फतेह जहान सिंह, लावण्या ईरा और रणविजय सिंह ने इस इवेंट को इमोशनल महत्व दिया। इस उपलब्धि से स्कूबा डाइविंग, मरीन टूरिज्म और आइलैंड्स की ग्लोबल पहचान को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
- गुजरात में NH-48 के सूरत-भरूच हिस्से में चोरयासी टोल प्लाजा पर अपना पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) टोलिंग सिस्टम शुरू किया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा शुरू की गई यह प्रणाली वाहनों को बिना रुके टोल प्वाइंट से गुजरने में सक्षम बनाती है, जिससे टोल संग्रह पूरी तरह से स्वचालित और संपर्क रहित हो जाता है। पहले दिन, लगभग 41,500 वाहनों ने निर्बाध रूप से टोल पार किया। यह प्रणाली टोल कटौती के लिए स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (ANPR) और FASTag तकनीक का उपयोग करती है। प्रमुख लाभों में यातायात की भीड़ में कमी, ईंधन दक्षता में सुधार, वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में कमी और अधिक पारदर्शिता शामिल हैं। NHAI ने ई-नोटिस अनुपालन नियम भी पेश किए हैं।
- सिक्किम भारत की पहली पूरी तरह से पेपरलेस ज्यूडिशियरी बन गई है, जैसा कि भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने गंगटोक में टेक्नोलॉजी और ज्यूडिशियल एजुकेशन पर नेशनल कॉन्क्लेव के दौरान अनाउंस किया। यह अचीवमेंट भारत के डिजिटल जस्टिस ट्रांसफॉर्मेशन में एक बड़ा कदम है, जिससे कोर्ट बिना फिजिकल पेपरवर्क के काम कर सकेंगी। इस सिस्टम के तहत, नागरिक ई-फाइलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिजिटल रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हैं, वर्चुअल हियरिंग में शामिल हो सकते हैं और केस को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। यह इनिशिएटिव इस विज्ञान के साथ है कि "पिटीशन आगे बढ़नी चाहिए, लोग नहीं," जिससे दूर-दराज के इलाकों में जस्टिस तक पहुंच बेहतर होगी।
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बचपन में डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए एक बड़ा नेशनल फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, जिसमें जन्म से लेकर 18 साल तक के बच्चे शामिल हैं। यह पहल डायबिटीज़ से जुड़ी दिक्कतों और मौतों को कम करने के लिए शुरुआती स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस, इलाज और लंबे समय तक देखभाल पर फोकस करती है। हाल ही में जारी "बच्चों में डायबिटीज़ मेलिटस पर गाइडेंस डॉक्यूमेंट" कम्प्युनिटी स्क्रीनिंग, ज़िला अस्पतालों और एडवांस्ड मेडिकल केयर को मिलाकर एक स्टैंडर्ड देशव्यापी तरीका पेश करता है। सरकार ने टाइप 1 डायबिटीज़ के लक्षणों को जल्दी पहचानने में मदद के लिए 4Ts अवेयरनेस मॉडल — टॉयलेट, प्यासा, थका हुआ और पतला होना — को बढ़ावा दिया है।

- विधानसभा चुनाव के नतीजे 2026 ने कई भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बड़े राजनीतिक बदलाव लाए। पश्चिम बंगाल में, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 206 सीटें जीतीं, जिससे ममता बनर्जी का 15 साल का शासन खत्म हो गया, क्योंकि AITC को सिर्फ 80 सीटें मिलीं। तमिलनाडु में, एक्टर-पॉलिटिशियन विजय थलपति की तमिलगा वेट्टी कज़गम (TVK) DMK और ADMK से आगे, 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। केरल में, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) ने LDF को हराकर एक दशक के लेफ्ट शासन का अंत किया। इस बीच, BJP के नेतृत्व वाले NDA ने असम में 100 से ज़्यादा गठबंधन सीटों के साथ सत्ता बरकरार रखी और नॉर्थईस्ट में अपना दबदबा बनाए रखा। पुडुचेरी में, एन. रंगासामी के नेतृत्व वाली NDA सरकार ने कामयाबी से सत्ता बरकरार रखी।
- झारखंड का हज़ारीबाग ज़िला भारत का पहला और इकलौता मोती खेती वाला क्लस्टर बनने वाला है, जिसे सरकार और मछली पालन विभाग साइंटिफिक एक्वाकल्चर और ग्रामीण रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। इस पहल का मकसद हज़ारीबाग को मॉडर्न खेती की तकनीकों, मार्केट लिंकेज और धीरे-धीरे बढ़ाकर टिकाऊ और फ़ायदेमंद मोती की खेती के लिए एक मॉडल हब बनाना है। इसमें महिला सशक्तिकरण पर खास ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें सेल्फ-हेल्प ग्रुप (SHG) को ट्रेनिंग दी जा रही है और एक ऑल-वीमेन फ़ार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइज़ेशन (FPO) बनाने की योजना चल रही है। यह प्रोजेक्ट किसानों की इनकम में अलग-अलग तरह की चीज़ें लाने के लिए तिलैया रिज़र्वॉयर में मोती की खेती को केज फ़िश कल्चर के साथ भी जोड़ता है। मोती की खेती, जिसमें कंट्रोल्ड पानी की कंडीशन में सीप की खेती शामिल है, रोज़गार, एक्सपोर्ट और ग्रामीण आर्थिक विकास के लिए मज़बूत पोटेन्शियल देती है।
- यूनियन कैबिनेट ने 5 मई, 2026 को सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) अमेंडमेंट बिल, 2026 को मंजूरी दी। इसमें भारत के सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने का प्रस्ताव है, जिसमें भारत के चीफ जस्टिस (CJI) भी शामिल हैं। इस अमेंडमेंट का मकसद सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) एक्ट, 1956 में बदलाव करना है ताकि बढ़ते केसों की संख्या को कम किया जा सके और न्यायिक क्षमता में सुधार किया जा सके। अभी, कोर्ट में CJI के अलावा 33 जज हैं, और प्रस्ताव का मकसद इसे CJI के अलावा 37 जजों तक बढ़ाना है। संविधान के आर्टिकल 124(1) के तहत, संसद के पास सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या तय करने का अधिकार है। इस कदम से उम्मीद है कि इससे सुनवाई तेज़ होगी, केसों का निपटारा तेज़ी से होगा और जजों पर काम का बोझ कम होगा, जिससे भारत का न्यायिक सिस्टम मज़बूत होगा।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात में 3,936 करोड़ रुपये से अधिक के संयुक्त निवेश के साथ भारत सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) के तहत दो नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। परियोजनाओं से 2,200 से अधिक कुशल नौकरियों का सृजन होने और भारत के वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनने के लक्ष्य को मज़बूत करने की उम्मीद है। धोलेरा में क्रिस्टल मैट्रिक्स लिमिटेड (सीएमएल) की एक परियोजना भारत की पहली मिनी/माइक्रो-एलईडी और गैलियम नाइट्राइड ( GaN ) सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा स्थापित करेगी, जो उन्नत प्रदर्शन प्रौद्योगिकियों और स्मार्ट उपकरणों का समर्थन करेगी। सूरत में सुची सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड (एसएसपीएल) की दूसरी परियोजना एक ओएसपीटी (आउटसोर्सर्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट) सुविधा स्थापित करेगी, जिसकी उत्पादन क्षमता सालाना 1 बिलियन से अधिक चिप्स की होगी

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लगभग ₹ 1,570 करोड़ के निवेश के साथ गुजरात के वडिनार में एक अत्याधुनिक जहाज मरम्मत सुविधा को मंजूरी दी है। भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और विदेशी शिपयार्ड पर निर्भरता कम करने के लिए यह परियोजना दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित की जाएगी। मुंद्रा और कांडला जैसे प्रमुख बंदरगाहों के पास स्थित, अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गों के साथ वडिनार की रणनीतिक स्थिति बड़े जहाजों की सर्विसिंग के लिए इसे आदर्श बनाती है। इस सुविधा में 650 मीटर की जेट्टी, दो फ्लोटिंग ड्राई डॉक और 300 मीटर लंबे जहाजों की मरम्मत करने में सक्षम उन्नत समुद्री कार्यशालाएं शामिल होंगी। इस परियोजना से लगभग 290 प्रत्यक्ष और 1,100 अप्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन होने की उम्मीद है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कपास की पैदावार, गुणवत्ता, स्थिरता और किसानों की आय में सुधार के लिए 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए कपास उत्पादकता के लिए ₹ 5,659.22 करोड़ के मिशन को मंजूरी दी। मिशन का उद्देश्य सरकार की 5F रणनीति - खेत से फाइबर से फैक्ट्री से फैशन से विदेशी तक के तहत पूरे कपास मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है। प्रमुख फोकस क्षेत्रों में उच्च उपज और जलवायु-लचीले बीज विकसित करना, आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देना, कपास की गुणवत्ता और प्रसंस्करण में सुधार, परीक्षण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और कस्तूरी कपास भारत के माध्यम से ब्रांडिंग का समर्थन करना शामिल है। मिशन आईसीएआर संस्थानों, सीएसआईआर और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के समर्थन से 14 राज्यों में 140 जिलों को कवर करेगा।
- केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर नए साउथ कोस्ट रेलवे (SCoR) ज़ोन के निर्माण को नोटिफाई कर दिया है, जिसका हेडक्वार्टर विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में होगा, और यह ज़ोन 1 जून, 2026 से चालू हो जाएगा। रेलवे एक्ट, 1989 के तहत बना यह नया ज़ोन ईस्ट कोस्ट रेलवे और साउथ सेंट्रल रेलवे को रीऑर्गेनाइज़ करके बनाया गया है। इसमें साउथ सेंट्रल रेलवे के गुंटकल, गुंटूर और विजयवाड़ा डिवीज़न के साथ-साथ रीऑर्गेनाइज़्ड वाल्टेयर डिवीज़न भी शामिल होगा, जो विशाखापत्तनम डिवीज़न बन जाएगा। इसके अलावा, ईस्ट कोस्ट रेलवे के तहत एक नया रायगढ़ डिवीज़न बनाया जाएगा।
- समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने और स्कूली बच्चों में विकलांगता की प्रारंभिक पहचान का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने PRASHAST 2.0 शुरू किया है। अपग्रेड किया गया डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसे प्री-असेसमेंट होलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल (PRASHAST) कहा जाता है, शिक्षकों और स्कूलों को विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत मान्यता प्राप्त 21 प्रकार की विकलांगताओं के लिए छात्रों की स्क्रीनिंग करने में मदद करता है। मोबाइल और वेब दोनों प्रारूपों में उपलब्ध यह टूल प्रारंभिक चरण में सीखने और विकासात्मक चुनौतियों की पहचान करने के लिए शिक्षकों और विशेष शिक्षकों को शामिल करते हुए दो-स्तरीय स्क्रीनिंग प्रक्रिया का पालन करता है। PRASHAST 2.0 को UDISE+, APAAR ID और स्वावलंबन कार्ड पोर्टल जैसी प्रणालियों के साथ एकीकृत किया गया है,
- वंदे मातरम को 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, जिसे 150 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्रीय कैबिनेट ने नेशनल ऑनर के अपमान की रोकथाम

- एक्ट में बदलाव करके इस गाने को नेशनल एंथम, जन गण मन के बराबर कानूनी सुरक्षा देने का प्रस्ताव रखा है। असल में संस्कृत में बंगाली में लिखा गया और आनंदमठ नॉवेल में छपा, वंदे मातरम भारत की आज़ादी की लड़ाई और राष्ट्रवादी आंदोलन का एक मजबूत निशान बन गया। हालांकि इसे 1950 में नेशनल सॉन्ग के तौर पर पहचान मिली, लेकिन अभी इसे नेशनल एंथम जैसे कानूनी सुरक्षा उपाय नहीं मिले हैं।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ( MoHFW ) ने डिजिटल मॉनिटरिंग और इंटीग्रेटेड हेल्थ रिकॉर्ड के ज़रिए माँ और बच्चे की हेल्थकेयर को मजबूत करने के लिए जननी (जर्नी ऑफ़ एंटेनाटल, नेटल एंड नियोनेटल इंटीग्रेटेड केयर) प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म एंटीनेटल केयर, चाइल्डबर्थ, पोस्टनेटल केयर, न्यूबोर्न केयर, छोटे बच्चों की हेल्थकेयर और फ़ैमिली प्लानिंग सर्विसेज़ जैसे स्टेज में हेल्थकेयर सर्विसेज़ को ट्रेक करेगा। जननी का मकसद माँ और बच्चों के लिए एक सेंट्रलाइज़्ड डिजिटल सिस्टम बनाकर हेल्थकेयर की पहुँच, कंटिन्यूटी और प्रेग्रेसी या बच्चे के हेल्थ रिस्क का जल्दी पता लगाना है। यह पहल आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और ई-हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम जैसे प्रोग्राम के तहत भारत के बड़े डिजिटल हेल्थकेयर को सपोर्ट करती है।
  - सीएसआईआर-केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को जीवन-अंत प्लास्टिक कचरे से बने टेक्निकल टेक्सटाइल जियोसेल्स का उपयोग करके भारत का पहला रोडब्लॉक सेक्शन विकसित करने के लिए इंडिया बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स से मान्यता मिली। नई दिल्ली में प्रदर्शित इस परियोजना में प्रबंधन में मुश्किल प्लास्टिक कचरे को टिकाऊ सड़क अवसंरचना सामग्री में परिवर्तित किया जाता है। ये पुनर्जीवीकृत जियोसेल्स, जो छत्ते के आकार की संरचनाएँ हैं, सड़कों को मजबूत करने और मिट्टी को स्थिर करने के लिए उपयोग की जाती हैं, टिकाऊ बुनियादी ढांचे का समर्थन करती हैं और प्लास्टिक कचरे का उत्पादक रूप से पुनः उपयोग करके परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती हैं। यह पहल पर्यावरण के अनुकूल सड़क इंजीनियरिंग समाधानों के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और उद्योग के बीच सफल सहयोग पर भी प्रकाश डालती है।
  - यूनिनयन लेबर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन नेटवर्क के ज़रिए नए लेबर कोड्स के तहत 40 साल और उससे ज़्यादा उम्र के वर्कर्स के लिए देश भर में फ्री सालाना हेल्थ चेक-अप प्रोग्राम शुरू किया। नई दिल्ली के ESIC मेडिकल कॉलेज में शुरू की गई इस पहल का फोकस प्रिवेंटिव हेल्थकेयर, बीमारी का जल्दी पता लगाना, ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सोशल सिक्योरिटी को बढ़ाना है। खतरनाक इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले वर्कर्स की उम्र चाहे जो भी हो, ज़रूरी मेडिकल स्क्रीनिंग होगी। यह प्रोग्राम चार लेबर कोड्स को लागू करने में मदद करता है, जिसका मकसद पूरे भारत में वर्कर वेलफेयर, हेल्थकेयर एक्सेस और फॉर्मल सोशल सिक्योरिटी कवरेज को बेहतर बनाना है।
  - 9-10 मई, 2026 को नई दिल्ली में भारत के पहले इंटरनेशनल ऑपथ्लोमोलॉजी रिसर्च कॉन्फ़्रेंस, AIOS-AFOU 2026 का उद्घाटन करेंगे। आर्मी हॉस्पिटल (रिसर्च एंड रेफरल) और ऑल इंडिया ऑपथ्लोमोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा आयोजित यह कॉन्फ़्रेंस AI-ड्रिवन डायग्नोस्टिक्स, रेटिनल इमेजिंग, डायबिटिक रेटिनोपैथी, कॉर्नियल बीमारियों, आंखों की चोटों और मिलिट्री ऑपथ्लोमोलॉजी पर फोकस करेगी। AIIMS नई दिल्ली जैसे बड़े संस्थान और हरमिंदर सिंह दुआ और कॉलिन सियांग हुई टैन जैसे ग्लोबल एक्सपर्ट इसमें हिस्सा लेंगे, जिससे एडवांस्ड आई केयर रिसर्च में इनोवेशन और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।

- अपार सक्सेना ने यूरोपियन चैस टूर्नामेंट में तीनों ज़रूरी IM नॉर्म्स हासिल करके मशहूर इंटरनेशनल मास्टर (IM) टाइटल जीता है। FIDE से मिलने वाला IM टाइटल ग्रैंडमास्टर के बाद दुनिया के सबसे बड़े चैस टाइटल्स में से एक है और इसके लिए मज़बूत इंटरनेशनल प्लेयर्स के खिलाफ लगातार अच्छा परफॉर्म करने के साथ-साथ अच्छी FIDE रेटिंग की भी ज़रूरत होती है। अपार की यह कामयाबी दुनिया के चैस में भारत के बढ़ते दबदबे को दिखाती है, जिसे बेहतर कोचिंग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल एक्सपोजर और युवाओं की बढ़ती भागीदारी से बढ़ावा मिला है, साथ ही यह भारत में चैस टैलेंट के एक बड़े सेंटर के तौर पर कर्नाटक की रेप्युटेशन को भी मज़बूत कर रहा है।
- भारत ने आने वाली 2027 की जनगणना के तहत जनगणना करने वालों के लिए QR-कोड वाले पहचान पत्र शुरू किए हैं ताकि पारदर्शिता, सुरक्षा और डिजिटल वेरिफिकेशन को बेहतर बनाया जा सके। नागरिक स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके QR कोड स्कैन करके गिनती करने वालों को वेरिफाई कर सकते हैं, जिससे फ़िल्ड विज़िट के दौरान किसी और की नकल को रोकने में मदद मिलती है। टेक्नोलॉजी से चलने वाले जनगणना सिस्टम में मोबाइल ऐप, सेंट्रलाइज़्ड पोर्टल, रियल-टाइम मॉनिटरिंग और खुद गिनती करने की सुविधाएं शामिल हैं। पहला फेज़ 1 अप्रैल, 2026 को शुरू हुआ, जिसमें देश भर के लगभग 30 लाख गिनती करने वाले शामिल हुए। जनगणना एक्ट, 1948 के तहत की गई यह पहल डिजिटल गवर्नेंस, पेपरलेस एडमिनिस्ट्रेशन और अच्छे डेटा कलेक्शन की दिशा में भारत के बड़े कदम को सपोर्ट करती है।
- सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया के एक प्रस्ताव के बाद, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन 2027-28 के इलेक्शन साइकिल से सिर्फ़ महिलाओं के लिए एक परमानेंट वाइस-प्रेसिडेंट पोस्ट ला सकता है, ताकि लीगल लीडरशिप में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बेहतर हो सके। कोर्ट ने रिप्रेजेंटेशन के महत्व पर महिला वकीलों की आपत्तियों के बाद 2026-27 के SCBA इलेक्शन में सेक्रेटरी पोस्ट और चुनी हुई एग्जीक्यूटिव कमेटी सीटों के लिए पहले के रिज़र्वेशन को भी बहाल कर दिया। इस प्रस्ताव का मकसद बार बाँड़ी गवर्नेंस में जेंडर इनक्लूसिविटी, लीडरशिप के मौकों और महिला वकीलों की भागीदारी को मज़बूत करना है और यह भारत में लीगल इंस्टीट्यूशन में इसी तरह के सुधारों पर असर डाल सकता है।

### राज्य समाचार

- विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद, हिमंत बिस्वा सरमा ने गुवाहाटी के लोक भवन में गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को असम के मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया है। गवर्नर ने सरमा और उनकी कैबिनेट से अनुरोध किया कि जब तक नई सरकार आधिकारिक तौर पर नहीं बन जाती, तब तक वे केयरटेकर के तौर पर काम करते रहें। BJP की अगुवाई वाली NDA को राज्य में भारी जीत मिली है, और सूत्रों से पता चलता है कि सरमा के मुख्यमंत्री बने रहने की संभावना है, और शपथ ग्रहण समारोह 12 मई, 2026 को होने की उम्मीद है। संवैधानिक परंपरा के अनुसार, मुख्यमंत्री चुनाव के बाद इस्तीफा देते हैं ताकि गवर्नर नए चुने गए विधायक दल के नेता को सरकार बनाने के लिए बुला सकें। BJP ने विधायक दल का नेता चुनने के लिए जेपी नड्डा और नायब सिंह सैनी को ऑब्जर्वर नियुक्त किया है, जबकि सहयोगी AGP ने सरमा की उम्मीदवारी का समर्थन किया है।

- नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा के मुताबिक, 2022-2024 के दौरान, बंगलुरु में हर एक लाख आबादी पर लगभग 20 सुसाइड के साथ, बड़े भारतीय शहरों में सबसे ज्यादा सुसाइड रेट दर्ज किया गया। भारत में एकसीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स रिपोर्ट से पता चला कि बंगलुरु में 2024 में 2,403 सुसाइड रिकॉर्ड किए गए, जबकि दिल्ली में कुल मामले ज्यादा थे लेकिन ज्यादा आबादी की वजह से सुसाइड रेट कम था। मुख्य कारणों में पारिवारिक समस्याएं, बीमारी, मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं, आर्थिक तनाव, काम का दबाव, माइग्रेशन का तनाव और सोशल आइसोलेशन शामिल थे, जिससे शहरों में बढ़ती मेंटल हेल्थ की चिंताएं और बेहतर काउंसलिंग और सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया।
- सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री चुने गए, जिससे ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का 15 साल का राज खत्म हो गया। यह घोषणा अमित शाह ने कोलकाता में BJP विधायक दल की मीटिंग के दौरान की। अधिकारी, जो 2020 में TMC छोड़कर BJP में शामिल हुए थे, ने पहले नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया था और बंगाल में BJP की बढ़त का एक अहम चेहरा बनकर उभरे थे। रिपोर्ट्स में एक महिला नेता समेत दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने का भी सुझाव दिया गया है।
- ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में “सहकार से समृद्धि” के विज़न के तहत अपना पहला रीजनल कोऑपरेटिव रिफॉर्म कॉन्फ्रेंस होस्ट किया। मिनिस्ट्री ऑफ़ कोऑपरेशन द्वारा ऑर्गनाइज़ किए गए इस इवेंट का फोकस नॉर्थ-ईस्ट में कोऑपरेटिव बैंकिंग, डेयरी, फिशरीज़, अनाज स्टोरेज, PACS एक्सपेंशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग और मार्केट लिंकेज को मज़बूत करना था। इसमें सभी नॉर्थ-ईस्ट राज्यों और NABARD और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जैसे इंस्टीट्यूशन के रिप्रेजेंटेटिव ने हिस्सा लिया। चर्चाओं में कोऑपरेटिव-लेड रूरल डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट, महिला एंटरप्रेन्योरशिप और इनक्लूसिव ग्रोथ और लोकल इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के सबसे बड़े अनाज स्टोरेज प्लान पर ज़ोर दिया गया।
- मार्च 2025 से मार्च 2026 तक घर पूरा करने की रैंकिंग में ओडिशा प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है। सितंबर 2024 में शुरू की गई इस योजना के तहत, ओडिशा ने 24,625 घरों को मंजूरी दी, 23,464 जगहों को जियो-टैग किया, 3,134 घरों पर नींव का काम शुरू किया और मई 2026 तक 2,008 घर पूरे कर लिए। यह उपलब्धि राज्य के सस्ते शहरी घरों को मज़बूती से लागू करने, डिजिटल मॉनिटरिंग, जियो-टैगिंग टेक्नोलॉजी और आर्थिक रूप से कमज़ोर और मध्यम आय वाले परिवारों को पक्के घर देने के लिए शहरी स्थानीय निकायों की मिलकर की गई कोशिशों को दिखाती है।
- नीति आयोग और यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस के डेटा के मुताबिक, झारखंड ने 2024-25 में 0% प्राइमरी ड्रॉपआउट रेट रिकॉर्ड करके एजुकेशन में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। राज्य ने 2014-15 में प्राइमरी ड्रॉपआउट को 6.41% से घटाकर जीरो कर दिया, जबकि अपर प्राइमरी ड्रॉपआउट 7.42% से घटकर 1.7% और सेकेंडरी ड्रॉपआउट 23.2% से घटकर 3.5% हो गया। झारखंड सेकेंडरी ड्रॉपआउट में कमी के मामले में देश भर में चौथे नंबर पर रहा, जो टीचर की खाली जगह और स्कूल न जाने वाले बच्चों जैसी चुनौतियों के बावजूद, स्टूडेंट के बने रहने, स्कूल में हिस्सा लेने और पढ़ाई तक पहुंच में अच्छी तरक्की दिखाता है।

- सुवेंदु अधिकारी ने 9 मई, 2026 को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में नरेंद्र मोदी और NDA के सीनियर नेताओं की मौजूदगी में आज़ादी के बाद पश्चिम बंगाल के पहले BJP मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी ने 294 सदस्यों वाली विधानसभा में 207 सीटें जीतीं, जिससे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस सरकार का 15 साल का राज खत्म हो गया। 2020 में BJP में शामिल हुए अधिकारी ने इससे पहले नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया था। यह जीत पूर्वी भारत में एक बड़े राजनीतिक बदलाव का प्रतीक है और "सोनार बांग्ला" विकास विज्ञान के तहत BJP की राष्ट्रीय मौजूदगी को मज़बूत करती है।
- महाराष्ट्र ने रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट-टू-एनर्जी सिस्टम और सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ावा देने के लिए कम्प्रेसड बायोगैस (CBG) पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी है, और FY 2026-27 के लिए ₹ 500 करोड़ दिए हैं। इस पॉलिसी का मकसद हर ज़िले में म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट और खेती के बचे हुए हिस्से का इस्तेमाल करके एनारोबिक डाइजेशन के ज़रिए साफ़ फ़्यूल बनाने के लिए CBG प्रोजेक्ट्स लगाना है। इसमें PPP और हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल, हर प्रोजेक्ट के लिए ₹ 15 करोड़ तक की वायबिलिटी गैप फंडिंग, ज़रूरी वेस्ट सेग्रीगेशन और प्रायोरिटी यूटिलिटी सपोर्ट शामिल हैं। SATAT और स्वच्छ भारत मिशन जैसी स्कीमों से जुड़ी यह पहल भारत के नेट-ज़ीरो 2070 लक्ष्यों और सर्कुलर इकॉनमी की कोशिशों को सपोर्ट करती है।
- पहली बार BJP की सरकार बनी, जब 9 मई, 2026 को विधानसभा चुनाव में BJP की 207 सीटों पर बड़ी जीत के बाद सुवेंदु अधिकारी ने 9वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह में दिलीप घोष, अग्निमित्र पॉल, अशोक कीर्तनिया, क्षुदिराम टुडू और निसिथ प्रमाणिक जैसे मंत्री भी शामिल हुए। कैबिनेट में BJP का क्षेत्रीय, आदिवासी, मत्तुआ, महिलाओं और उत्तर बंगाल के प्रतिनिधित्व पर फोकस दिखता है, और जल्द ही कैबिनेट में और विस्तार की उम्मीद है।

### अंतरराष्ट्रीय समाचार

- क्लूज़ शिप ट्रेवल से जुड़े हाल के हैन्टावायरस मामलों पर चिंता जता रहे हैं। हैन्टावायरस एक रेयर लेकिन जानलेवा बीमारी है जो ज़्यादातर चूहों के यूरिन, लार, बीट या हवा में मौजूद खराब पार्टिकल्स के कॉन्टैक्ट में आने से फैलती है। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि क्लूज़ शिप के बंद माहौल में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है और इन्फेक्शन का पता लगाना मुश्किल हो सकता है। शुरुआती लक्षणों में बुखार, मांसपेशियों में दर्द, थकान, सिरदर्द, जी मिचलाना और उल्टी शामिल हैं, जो तेज़ी से हैन्टावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम (HPS) में बदल सकते हैं, जिससे फेफड़ों में गंभीर दिक्कतें हो सकती हैं। अभी इसका कोई खास एंटीवायरल इलाज नहीं है, इसलिए जल्दी डायग्नोसिस और सपोर्टिव केयर बहुत ज़रूरी है।
- 2026 में एयर पॉल्यूशन दुनिया भर में एक बड़ी चिंता बन जाएगा, कई शहरों में अचानक खतरनाक रूप से हाई एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) लेवल रिकॉर्ड किया गया है। हाल की रैंकिंग के अनुसार, कोभ (आयरलैंड) 208 के AQI के साथ लिस्ट में सबसे ऊपर है, उसके बाद आयरलैंड में डुंगरवन और क्लोनमेल हैं, जबकि काशगर (चीन), बीकानेर, पटना, औरंगाबाद और मुजफ्फरपुर (भारत) जैसे शहरों में भी खराब पॉल्यूशन लेवल रिपोर्ट किया गया है। एक्सपर्ट्स इस बढ़ती हुई के लिए मौसम में ठहराव, हवा का कम बहाव, कंस्ट्रक्शन की धूल, गाड़ियों से निकलने वाला एमिशन, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और रेगिस्तान के धूल के कणों जैसे फैक्टर्स को जिम्मेदार मानते हैं। भारत में, तेज़ी से

- शहरीकरण और ट्रैफिक जाम की वजह से कई शहरों में एयर क्वालिटी खराब हो रही है।
- जून 2026 में भारत की BRICS प्रेसीडेंसी में इंदौर BRICS एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग होस्ट करेगा, जिसमें BRICS देशों — ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका के मिनिस्टर एक साथ आएंगे। मीटिंग में फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट-रेज़िलिएंट एग्रीकल्चर, डिजिटल फार्मिंग, एग्रीकल्चर में AI, सस्टेनेबल इरिगेशन, एग्रीकल्चरल ट्रेड और किसान कल्याण पर फोकस होगा। भारत का मकसद फूड सिस्टम पर ग्लोबल सहयोग को मज़बूत करते हुए स्मार्ट फार्मिंग और एग्रीकल्चरल इनोवेशन में अपनी तरक्की दिखाना है। समिट होस्ट करने से एग्रीकल्चर, ट्रेड और स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के एक बड़े सेंटर के तौर पर इंदौर की इंटरनेशनल प्रोफाइल भी बढ़ेगी।
- इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने लॉस एंजिल्स 2028 समर ओलंपिक्स से पहले बेलारूस पर लगी रोक हटा दी है, जिससे बेलारूसी एथलीट और टीमों ऑफिशियली इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, ओपनिंग सेरेमनी और मेडल इवेंट में हिस्सा ले सकेंगी। हालांकि, रूस पर रोक अभी भी लगी हुई है, रूसी एथलीट को बिना नेशनल सिंबल के और सख्त एलिजिबिलिटी शर्तों के तहत सिर्फ न्यूट्रल कॉम्पिटिटर के तौर पर इजाज़त है। यूक्रेन विवाद और वर्ल्ड एंटी-डोपिंग एजेंसी द्वारा उठाए गए एंटी-डोपिंग मुद्दों की चिंताओं के कारण रूसी ओलंपिक कमेटी का सस्पेंशन जारी है। इस बीच, वर्ल्ड एथलेटिक्स ने रूसी और बेलारूसी दोनों एथलीटों पर रोक जारी रखने का फैसला किया है।
- 24 अप्रैल, 2026 को पहली SME वर्किंग ग्रुप मीटिंग आयोजित करके अपनी BRICS चेरशिप 2026 के तहत एक नए MSME सहयोग एजेंडे को आगे बढ़ाया है। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज मंत्रालय के नेतृत्व में, वर्चुअल मीटिंग में MSME की फाइनेंस तक पहुंच, फिनटेक-ड्रिवन क्रेडिट इकोसिस्टम, डिजिटल लेंडिंग, फाइनेंशियल इनक्लूजन और क्रॉस-बॉर्डर ट्रेड पेमेंट पर फोकस किया गया। नई इंडस्ट्रियल क्रांति पर BRICS पार्टनरशिप के तहत चर्चाओं में रोजगार, इनोवेशन, एक्सपोर्ट और इनक्लूसिव ग्रोथ में MSME की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। भारत BRICS देशों के बीच पॉलिसी कोऑर्डिनेशन और इंस्टीट्यूशनल सहयोग को मज़बूत करने के लिए पहले BRICS MSME फोरम की भी मेजबानी करेगा।

### समझौते/ MoU

- इंडियाAI ने भारत में AI से चलने वाले हेल्थकेयर इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च के साथ एक MoU साइन किया है। यह पार्टनरशिप इंडियाAI के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को ICMR की बायोमेडिकल रिसर्च एक्सपर्टिज़ के साथ जोड़ेगी ताकि एथिकल, स्केलेबल और रिसर्च-वेस्ट हेल्थकेयर AI सॉल्यूशन डेवलप किए जा सकें। एग्रीमेंट के तहत, MIDAS फ्रेमवर्क के ज़रिए डेवलप किए गए एनोनिमाइज़्ड हेल्थकेयर डेटासेट और AI टूल्स को AIKosh प्लेटफॉर्म पर होस्ट किया जाएगा, जिससे रिसर्चर्स और स्टार्टअप्स के लिए एक्सेस बेहतर होगा। इंडियाAI बीमारी की भविष्यवाणी, मेडिकल इमेजिंग, हेल्थकेयर एनालिटिक्स और ड्रग रिसर्च में AI एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए हाई-परफॉर्मंस कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी देगा, जिससे हेल्थकेयर में जिम्मेदार AI गवर्नेंस के लिए भारत की कोशिश मज़बूत होगी।

**बैंकिंग/अर्थव्यवस्था/व्यापार समाचार**

- फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने चेतावनी दी है कि एंथ्रोपिक्स माइथोस जैसे एडवांस्ड AI मॉडल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए गंभीर साइबर सिक्योरिटी खतरे पैदा कर सकते हैं। ये AI सिस्टम बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में कमजोरियों को तेजी से पहचान सकते हैं और उनका फायदा उठा सकते हैं, जिससे बैंकों के लिए उपलब्ध रिस्पोन्स टाइम कम हो जाता है। कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर, मोबाइल ऐप, API, क्लाउड सर्विस और पेमेंट सिस्टम सहित मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम आपस में बहुत जुड़े हुए हैं, जिससे वे AI से होने वाले हमलों के लिए कमजोर हो जाते हैं। सरकार ने बैंकों को IT सिक्योरिटी मजबूत करने, डेटा प्रोटेक्शन में सुधार करने और CERT-In और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ कोऑर्डिनेट करने की सलाह दी है। दुनिया भर में, जेपी मॉर्गन चैस, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसे इंस्टीट्यूशन AI-बेस्ड डिफेंस डेवलप कर रहे हैं। जोखिमों के बावजूद, AI टूल्स तेजी से खतरे का पता लगाने और ऑटोमेटेड सिक्योरिटी टेस्टिंग जैसे फायदे भी देते हैं।
- भारत ने 2 मई 2026 को अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण उपकरण) नियम, 2019 में संशोधन के माध्यम से स्वचालित मार्ग के तहत बीमा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति दी है। सुधार विदेशी निवेशकों को पूर्व सरकारी अनुमोदन के बिना बीमा कंपनियों और बिचौलियों का पूर्ण स्वामित्व लेने की अनुमति देता है। पात्र संस्थाओं में बीमा दलाल, टीपीए, सलाहकार, सर्वेक्षक और बीमा रिपॉजिटरी शामिल हैं। इस कदम का उद्देश्य भारत के बीमा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करते हुए वैश्विक पूंजी, प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता को आकर्षित करना है। निवेश भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा विनियमित रहेगा और कंपनियों को बीमा अधिनियम, 1938 का अनुपालन करना होगा। हालांकि, LIC के पास स्वचालित मार्ग के तहत अलग से 20% FDI कैप जारी रहेगी
- सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) के जारी डेटा के मुताबिक, FY26 में भारत का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 5.12% बढ़कर ₹ 23.40 ट्रिलियन से ज़्यादा हो गया। यह ग्रोथ एक मजबूत टैक्स बेस को दिखाती है, जिसे कॉर्पोरेट टैक्स और पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन दोनों से सपोर्ट मिला है, भले ही यह सरकार के ₹ 24.21 ट्रिलियन के रिवाइज्ड अनुमान से कम रहा हो। कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन लगभग ₹ 10.99 लाख करोड़ रहा, जबकि सिक्योरिटीज़ ट्रांज़ैक्शन टैक्स (STT) समेत पर्सनल इनकम टैक्स ने ₹ 12.41 ट्रिलियन का योगदान दिया, जो सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स बना रहा। इस बीच, ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़कर ₹ 28.12 लाख करोड़ हो गया, और रिफंड घटकर ₹ 4.71 ट्रिलियन रह गया।
- रोहित जैन ने 2 मई, 2026 को भारत सरकार और कैबिनेट की अपॉइंटमेंट्स कमिटी (ACC) से मंजूरी मिलने के बाद, तीन साल के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के नए डिप्टी गवर्नर का पद संभाला है। वे टी. रवी शंकर की जगह लेंगे और उनके पास सेंट्रल बैंकिंग का 34 साल से ज़्यादा का अनुभव है, वे 1991 में RBI में शामिल हुए थे। जैन ने पहले डिपार्टमेंट ऑफ़ सुपरविज़न के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चीफ जनरल मैनेजर के तौर पर काम किया था, और RBI के नई दिल्ली ऑफिस में सीनियर पदों पर रहे हैं। उन्होंने बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविज़न (BCBS) और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड (FSB) जैसे ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में भी भारत को रिप्रेजेंट किया है।

- किरण मजूमदार-शॉ ने अपनी भतीजी क्लेयर मजूमदार को बायोकाॅन की होने वाली उत्तराधिकारी के तौर पर चुना है, जो भारत की जानी-मानी बायोफार्मास्युटिकल कंपनियों में से एक में लीडरशिप में बदलाव की योजना का संकेत है। क्लेयर, जो अभी बिकारा थैरेप्यूटिक्स की फाउंडर और CEO हैं, को ग्लोबल बायोटेक्नोलॉजी में बहुत अनुभव है और उन्होंने पहले थर्ड रॉक वेंचर्स और रियोस मेडिसिन्स के साथ काम किया है। यह कदम बायोसिमिलर, बायोटेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तेज़ी से हो रही तरक्की के बीच बायोकाॅन के भविष्य के लिए तैयार लीडरशिप पर फोकस को दिखाता है। बायोकाॅन ने लीडरशिप रीस्ट्रक्चरिंग की भी घोषणा की है, जिसमें श्रीहास तांबे बायोकाॅन बायोलाॅजिक्स के CEO बनेंगे और सिद्धार्थ मित्तल जुलाई 2026 से सिंजीन इंटरनेशनल को लीड करेंगे।
- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया (NSE) ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स (EGRs) लॉन्च किए हैं, जो निवेशकों को सोने में निवेश करने का एक विनियमित और डिजिटल तरीका प्रदान करते हैं। EGRs सेबी-मान्यता प्राप्त वॉल्ट में संग्रहीत भौतिक सोने के खिलाफ जारी की गई इलेक्ट्रॉनिक प्रतिभूतियां हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की सुविधा के साथ भौतिक सोने की सुरक्षा को जोड़ती हैं। हाल ही में, NSE ने एक EGR में 1,000 ग्राम सोने की बार के सफल डीमटेरियलाइजेशन की घोषणा की। इन रसीदों को शेयरों की तरह स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार किया जा सकता है और लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन (LBMA) और भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा निर्धारित वास्तविक सोने के मानकों द्वारा समर्थित हैं। प्रमुख लाभों में सुरक्षित भंडारण, आसान लिक्विडिटी, चोरी का कम जोखिम और खुदरा निवेशकों के लिए पहुंच शामिल हैं। गोल्ड ईटीएफ के विपरीत, ईजीआर धारक अपनी रसीदों को सरेंडर करके सोने की भौतिक डिलीवरी लेना भी चुन सकते हैं।
- कुमार मंगलम बिडला को वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (Vi) का नया नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया है, जो 5 मई, 2026 से लागू होगा। यह अपॉइंटमेंट एक बड़े लीडरशिप बदलाव को दिखाता है क्योंकि टेलीकॉम कंपनी अपने बिज़नेस ऑपरेशन्स को मजबूत करने और लॉन्ग-टर्म रिवाइवल स्ट्रैटेजी पर फोकस कर रही है। पूर्व चेयरमैन रविंदर टक्कर ने इस पद से इस्तीफा दे दिया है और कंपनी के नॉन-एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन बने रहेंगे। आदित्य बिडला ग्रुप के चेयरमैन बिडला, वोडाफोन आइडिया के बनने के बाद से ही इसके साथ करीब से जुड़े रहे हैं और उम्मीद है कि अपनी लीडरशिप से वे इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ाएंगे।
- CRISIL के साथ जॉइंट "इंडिया फॉरवर्ड" रिपोर्ट में भारत के FY27 GDP ग्रोथ के अनुमान को 7.1% से घटाकर 6.6% कर दिया है। इसमें ग्लोबल इकाॅनमिक अनिश्चितता, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, रुपये में उतार-चढ़ाव, महंगाई का दबाव और वेस्ट एशिया विवाद का हवाला दिया गया है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि ब्रेंट क्रूड लगभग \$126 प्रति बैरल तक बढ़ गया है, जिससे भारत के इंपोर्ट बिल और महंगाई के आउटलुक के लिए रिस्क बढ़ गया है। धर्मकीर्ति जोशी ने तेल की बढ़ती कीमतों और कमजोर रुपये को इकाॅनमी के लिए "डबल व्हेमी" बताया, जबकि रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने FY27 में महंगाई 4.6% रहने का अनुमान लगाया है।

**नियुक्तियाँ/इस्तीफ़े**

- भारत सरकार ने 2 मई, 2026 को प्रसून जोशी को प्रसार भारती का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। साहित्य, विज्ञापन और सिनेमा में अपने योगदान के लिए जाने जाने वाले जोशी से भारत के पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम में इनोवेशन और क्रिएटिविटी लाने की उम्मीद है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने उनकी सांस्कृतिक समझ और लीडरशिप क्वालिटी पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उनकी तारीफ़ करते हुए उन्हें "अनोखी क्रिएटिव स्पिरिट" बताया। जोशी ने पहले CBFC चेयरपर्सन, मैककैन वर्ल्ड ग्रुप इंडिया के CEO और IGNCAs के ट्रस्टी के तौर पर काम किया है। प्रसार भारती, प्रसार भारती एक्ट, 1990 के तहत बना था, और ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन और डिजिटल वेब्स OTT प्लेटफॉर्म को देखता है।
- भारत सरकार ने आर बालासुब्रमण्यम और जोराम अनिया को नीति आयोग का फुल-टाइम सदस्य नियुक्त किया है, जिससे इसकी कोर टीम में सात सदस्य हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वीकृत इन नियुक्तियों का उद्देश्य शासन, जमीनी स्तर पर विकास, शिक्षा और सांस्कृतिक अध्ययन में विशेषज्ञता के साथ नीति निर्धारण को मजबूत करना है। अरुणाचल प्रदेश की एक शिक्षाविद जोराम अनिया, न्युथी समुदाय की पहली महिला हैं जिन्होंने PhD की है और उन्हें आदिवासी संस्कृति और स्वदेशी ज्ञान पर उनके काम के लिए जाना जाता है। SVYM और GRAAM के संस्थापक आर बालासुब्रमण्यम एक प्रसिद्ध नीति विशेषज्ञ और लेखक हैं। 2015 में स्थापित नीति आयोग, सहकारी संघवाद और नीति नवाचार को बढ़ावा देने वाले भारत के प्रमुख सार्वजनिक नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है।
- शशि शेखर वेम्पति को तीन साल के कार्यकाल के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जैसा कि 6 मई 2026 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने घोषणा की थी। वह प्रसून जोशी का स्थान लेंगे, जो हाल ही में प्रसार भारती के अध्यक्ष बने हैं। वेम्पति मीडिया, प्रौद्योगिकी, प्रसारण और सार्वजनिक संचार में अपनी मजबूत पृष्ठभूमि के लिए जाने जाते हैं और पहले प्रसार भारती के सीईओ के रूप में कार्यरत थे, जहाँ उन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी के आधुनिकीकरण का नेतृत्व किया था। IIT बॉम्बे के पूर्व छात्र, उन्होंने AI, शिक्षा और विज्ञान संचार की पहलों में भी योगदान दिया है, जिसमें AI4India Org की सह-स्थापना भी शामिल है।
- 8 मई, 2026 को कर्नाटक में एडमिशन ओवरसीइंग कमेटी (AOC) का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। AOC ट्रांसपेरेंसी और रेगुलेटरी ओवरसाइट पक्का करने के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेंटल और दूसरे प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन को सुपरवाइज़ करती है। जस्टिस हुद्वार ने पहले कर्नाटक हाई कोर्ट के एडिशनल और परमानेंट जज के तौर पर काम किया है, इसके अलावा प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज और कर्नाटक ज्युडिशियल एकेडमी के डायरेक्टर जैसे अहम पदों पर भी काम किया है। उनकी नियुक्ति जस्टिस बी. मनोहर का कार्यकाल पूरा होने के बाद हुई है और इससे राज्य में प्रोफेशनल एजुकेशन एडमिशन की मॉनिटरिंग मजबूत होने की उम्मीद है।

**रक्षा समाचार**

- भारत और कंबोडिया, दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए, 4 मई, 2026 को कंबोडिया के कम्पोंग स्पू प्रांत में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज़ CINBAX-II का दूसरा एडिशन शुरू करेंगे। दो हफ्ते की इस एक्सरसाइज़ में भारतीय सेना के 120 जवान शामिल होंगे, जिनमें ज्यादातर मराठा लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंट के होंगे, और रॉयल कंबोडियन आर्मी के 160 सैनिक होंगे। यह एक्सरसाइज़ आतंकवाद से लड़ने की क्षमता, मॉडर्न युद्ध कौशल और UN शांति मिशन जैसे हालात में जॉइंट ऑपरेशनल तैयारी को बढ़ाने पर फोकस करती है। मुख्य ट्रेनिंग एरिया में टैक्टिकल कॉम्बैट ड्रिल, ड्रोन ऑपरेशन, साइपर ट्रेनिंग और मोटार हैंडलिंग शामिल हैं।
- भारतीय सेना ने 7 मई 2026 को एक स्मारक वीडियो जारी किया, जो भारत के प्रमुख सीमा पार आतंकवाद विरोधी अभियानों में से एक, ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर था। 7 मई 2025 को आयोजित इस ऑपरेशन ने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे समूहों से जुड़े पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में नौ आतंकी शिविरों को निशाना बनाया। 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में ये हमले शुरू किए गए, जिसमें 26 भारतीय नागरिक मारे गए थे। आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार, लगभग 25 मिनट के भीतर 100 से अधिक आतंकवादियों को निष्प्रभावी कर दिया गया। वर्षगांठ के वीडियो में आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति पर प्रकाश डाला गया, जिसमें समन्वित सैन्य योजना, सटीक हमले और सेना, नौसेना और वायु सेना को शामिल करते हुए विकसित आतंकवाद विरोधी सिद्धांत का प्रदर्शन किया गया।
- डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन और इंडियन एयर फोर्स ने ओडिशा तट पर SEPECAT जगुआर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करके टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन (TARA) वेपन सिस्टम का पहला फ्लाइट ट्रायल सफलतापूर्वक किया। रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा डेवलप किया गया TARA, भारत का पहला स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम है जो पारंपरिक बमों को प्रिसिजन-गाइडेड स्टैंड-ऑफ वेपन में बदलता है। ट्रायल ने इसके गाइडेंस, नेविगेशन, एयरोडायनामिक परफॉर्मेंस और कंट्रोल सिस्टम को वैलिडेट किया, जिससे भारत की प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी बढ़ी, इम्पोर्टेड हथियारों पर डिपेंडेंस कम हुई और आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट मिला। रक्षा पहल।
- एनएस राजा सुब्रमणि को भारत का अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपॉइंट किया गया है और वे 30 मई को अनिल चौहान की जगह पदभार संभालेंगे। पूर्व वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड में मौजूदा मिलिट्री एडवाइजर, उन्होंने 1985 में गढ़वाल राइफल्स में कमीशन होने के बाद इंडियन आर्मी में लगभग 39 साल सेवा की। उनकी नियुक्ति चल रहे मिलिट्री सुधारों, थिएटराइजेशन, डिफेंस के लिए महत्वपूर्ण है। आधुनिकीकरण, और सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच मजबूत समन्वय।
- वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को अगला नेवल चीफ अपॉइंट किया गया है और वे 31 मई, 2026 को दिनेश के त्रिपाठी की जगह लेंगे। अभी वे वेस्टर्न नेवल कमांड को हेड कर रहे हैं, उन्हें 1987 में इंडियन नेवी में कमीशन मिला था और वे कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने पहले वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के तौर पर काम किया था और INS विक्रमादित्य और INS मैसूर जैसे बड़े वॉरशिप को कमांड किया था। उनका अपॉइंटमेंट ऐसे समय में हुआ है जब भारत मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंडो-पैसिफिक स्ट्रैटेजी, नेवल मॉडर्नाइजेशन और स्वदेशी डिफेंस कैपेबिलिटी को मजबूत कर रहा है।

### पुरस्कार और सम्मान

- दो भारतीय पत्रकारों, आरके आनंद और सुपर्णा शर्मा ने साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल निगरानी पर अपने खोजी कार्य के लिए सचित्र रिपोर्टिंग और टिप्पणी की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2026 जीता। उन्होंने ब्लूमबर्ग प्रोजेक्ट "ट्रैड" के लिए नताली ओबिको पियर्सन के साथ पुरस्कार साझा किया। रिपोर्ट ने एक भारतीय न्यूरोलॉजिस्ट की कहानी को उजागर किया जो एक "डिजिटल गिरफ्तारी" घोटाले में फंस गया था, जिसमें बताया गया था कि कैसे साइबर अपराधी पीड़ितों को दूर से हेरफेर करने के लिए तकनीक का दुरुपयोग करते हैं। परियोजना ने ऑनलाइन घोटालों, डिजिटल शोषण और निगरानी दुरुपयोग के बढ़ते खतरों को उजागर करने के लिए दृश्य कहानी, डेटा विश्लेषण और खोजी पत्रकारिता को जोड़ा। 4 मई 2026 को घोषित यह पुरस्कार पत्रकारिता में उत्कृष्टता को मान्यता देता है।
- कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस एंड असेसमेंट द्वारा ऑर्गनाइज़ किए गए कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड्स 2026 में साउथ एशिया रीजनल टाइटल जीता है। उन्हें एनवायरनमेंटल एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस और स्टूडेंट्स के बीच सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने में उनके शानदार काम के लिए पहचान मिली। अवार्ड्स के लिए 126 देशों से 12,000 से ज्यादा नॉमिनेशन आए, जिनमें से दुनिया भर में सिर्फ नौ रीजनल विनर चुने गए। मंडल का टीचिंग अप्रोच प्रैक्टिकल क्लाइमेट सॉल्यूशन, स्टूडेंट लीडरशिप और एनवायरनमेंटल ज़िम्मेदारी पर फोकस करता है। विनर के तौर पर, उन्हें £500 की किताबें, एक ट्रॉफी, ग्लोबल पहचान और भविष्य की कैम्ब्रिज टेक्स्टबुक्स में शामिल किया जाएगा।

### शिखर सम्मेलन

- 1-2 जून, 2026 को नई दिल्ली में पहली बार अंतरराष्ट्रीय बड़ी बिल्ली गठबंधन (IBCA) शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जो वन्यजीव संरक्षण के लिए अंतराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए वैश्विक नेताओं, वैज्ञानिकों और संरक्षणवादियों को एक साथ लाएगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घोषित शिखर सम्मेलन में सात प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों - बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। "बड़ी बिल्लियों को बचाओ, मानवता को बचाओ, पारिस्थितिकी तंत्र को बचाओ" विषय द्वारा निर्देशित, शिखर सम्मेलन का उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण के लिए वैश्विक रणनीतियों को बढ़ावा देना है। एक प्रमुख अपेक्षित परिणाम दिल्ली घोषणा को अपनाना है, जो कि विशेष रूप से बड़ी बिल्ली संरक्षण के लिए समर्पित पहली वैश्विक घोषणा है।

### खेल समाचार

- थॉमस कप 2026 में भारत का अभियान फ्रांस के खिलाफ 0-3 के सेमीफाइनल हार के साथ समाप्त हुआ, जिससे टीम को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सृजन वाली कोहनी के कारण लक्ष्य सेन की अनुपस्थिति महंगी साबित हुई क्योंकि भारत एक भी मैच जीतने में विफल रहा। आयुष शेटी क्रिस्टो पोपोव से 11-21, 9-21 से हार गए, जबकि किदांबी श्रीकांत को एलेक्स लैनियर ने 16-21, 18-21 से हराया। निर्णायक मैच में, एचएस प्रणय टोमा जूनियर पोपोव से 19-21, 16-21 से हार गए। फ्रांस ने अपने पहले थॉमस कप फाइनल में पहुंचकर

इतिहास रच दिया। हार के बावजूद, भारत ने एक और थॉमस कप कांस्य पदक के साथ अपनी मजबूत वैश्विक बैडमिंटन उपस्थिति बनाए रखी।

### योजनाएँ और समितियाँ समाचार

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट से प्रभावित व्यवसायों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) 5.0 को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य एयरलाइन क्षेत्र के लिए निर्धारित ₹ 5,000 करोड़ सहित ₹ 2.55 लाख करोड़ के लक्षित क्रेडिट प्रवाह के माध्यम से व्यापार निरंतरता और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना है। ECLGS 5.0 के तहत, सरकार राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) के माध्यम से MSMEs के लिए 100% क्रेडिट गारंटी कवरेज और गैर-MSMEs और एयरलाइंस के लिए 90% कवरेज प्रदान करेगी। पात्र व्यवसाय अपनी अधिकतम कार्यशील पूंजी के 20% तक अतिरिक्त ऋण का लाभ उठा सकते हैं।
- भारत की सबसे बड़ी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 9 मई, 2026 को 11 साल पूरे कर लिए हैं, जिससे भारत का सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क मजबूत हुआ है। PMJJBY में ₹ 2 लाख के लाइफ कवर के साथ 27.43 करोड़ एनरोलमेंट हुए, PMSBY में ₹ 2 लाख तक का एक्सीडेंट इश्योरेंस देते हुए 58 करोड़ एनरोलमेंट पार हो गए, जबकि APY में 60 साल बाद गारंटीड पेंशन देते हुए 9 करोड़ सव्सक्राइबर हो गए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फाइनेंशियल इनक्लूजन, सस्ता इश्योरेंस, पेंशन सिक्योरिटी और आसान डिजिटल एनरोलमेंट और क्लेम सिस्टम के ज़रिए कम इनकम वाले और असंगठित कामगारों को सपोर्ट देने में उनकी भूमिका पर ज़ोर दिया।

### विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार

- मिशन दृष्टि के प्रक्षेपण के साथ हासिल की, जो देश का सबसे बड़ा निजी तौर पर विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, जिसे बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप गैलेक्सआई द्वारा निर्मित किया गया है। 190 किलोग्राम के उपग्रह को स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट पर वैंडेनबर्ग, कैलिफोर्निया से लॉन्च किया गया था। मिशन दृष्टि में उन्नत ऑप्टोएसएआर प्रौद्योगिकी है, जो सभी मौसम और प्रकाश की स्थिति में उच्च गुणवत्ता वाली इमेजिंग के लिए इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल (ईओ) और सिंथेटिक एपर्चर रडार (एसएआर) प्रणालियों को जोड़ती है। उपग्रह रक्षा, कृषि, आपदा प्रबंधन, समुद्री सुरक्षा और शहरी नियोजन में अनुप्रयोगों का समर्थन करता है। भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र और IN-SPACE के समर्थन से, मिशन वैश्विक उपग्रह डेटा और भू-स्थानिक सेवाओं के बाजार में भारत की स्थिति को मजबूत करता है।
- जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में 120-किलोवाट के मैग्नेटोप्लाज़्मा डायनामिक (MPD) प्लाज़्मा इंजन का सफल टेस्ट किया, जो यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे ज्यादा पावर वाला इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन टेस्ट है। यह एडवांस्ड इंजन केमिकल फ्यूल के बजाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और लिथियम प्लाज़्मा का इस्तेमाल करता है, जिससे यह डीप-स्पेस मिशन के लिए बहुत एफिशिएंट है। NASA का मानना है कि यह टेक्नोलॉजी मंगल ग्रह की यात्रा के समय को नौ महीने से घटाकर 30-60 दिन कर सकती है, जिससे एस्ट्रोनॉट की सेफ्टी और मिशन की फीजिबिलिटी बेहतर होगी। यह टेस्ट मंगल ग्रह और दूसरे दूर के स्पेस मिशन पर लंबे समय तक इंसानी खोज के लिए भविष्य के न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन (NEP) सिस्टम को भी सपोर्ट करता है।

- पहली बार नई दिल्ली में "स्पेस सिस्टम और ऑपरेशन्स" पर इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन TC 20/SC 14 मीटिंग्स होस्ट कीं, जिसे ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने ऑर्गनाइज़ किया था। भारत मंडपम में हुए इस इवेंट में 13 देशों के 131 डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया, जिसमें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन, एकेडेमिया और ग्लोबल स्पेस एजेंसियों के एक्सपर्ट्स शामिल थे। चर्चा स्पेस सेफ्टी, सस्टेनेबिलिटी, इंटरऑपरैबिलिटी, मिशन ऑपरेशन्स और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर फोकस थी। अधिकारियों ने ग्लोबल स्पेस इकॉनमी में भारत की बढ़ती भूमिका पर ज़ोर दिया, जिसे रिफॉर्म, IN- SPACe के ज़रिए प्राइवेट पार्टिसिपेशन और कमर्शियल स्पेस एक्टिविटीज़ के विस्तार से सपोर्ट मिला है।

### महत्वपूर्ण दिन समाचार

- 2026 में इंटरनेशनल फायरफाइटर्स डे, 4 मई, 2026 को मनाया जाएगा। यह दुनिया भर में फायरफाइटर्स की हिम्मत, कुर्बानी और लगन को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। 1999 में शुरू हुआ यह दिन उन फायरफाइटर्स को भी श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने ज़ूटी करते हुए अपनी जान गंवाई। यह दिन 1998 में विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में हुई जंगल की आग की त्रासदी से शुरू हुआ था, जिसमें पांच फायरफाइटर्स की मौत हो गई थी। यह दिन फायरफाइटर्स के संरक्षक संत, सेंट फ्लोरियन के त्योहार के साथ मेल खाता है। खास निशानों में लाल और नीला रिबन शामिल है, जो आग और पानी को दिखाता है, और 'साउंड ऑफ़' परंपरा जिसमें सायरन और शांति शामिल है। समुदाय इस दिन को श्रद्धांजलि, जागरूकता अभियान और फायर सेफ्टी प्रोग्राम के ज़रिए मनाते हैं।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 4 मई से 10 मई, 2026 तक फायर सेफ्टी वीक 2026 शुरू किया है, जिसका फोकस अस्पतालों और पब्लिक इंस्टीट्यूशन में आग से बचने की तैयारी को बेहतर बनाना है। यह कैम्पेन केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव की अगुवाई में देश भर में शपथ के साथ शुरू हुआ और यह "सेफ स्कूल, सेफ हॉस्पिटल और फायर-सेफ्टी अवेयर सोसाइटी" थीम पर आधारित है। कैम्पेन के साथ-साथ, सरकार ने हेल्थकेयर सुविधाओं में आग और जीवन सुरक्षा पर नई नेशनल गाइडलाइंस भी पेश कीं, जिसमें रिस्क असेसमेंट, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, आग रोकने वाला इंप्रोस्ट्रक्चर, स्टाफ ट्रेनिंग और कंप्लायंस सिस्टम शामिल हैं। ICU, NICU, PICU और ऑपरेशन थिएटर जैसे हाई-रिस्क हॉस्पिटल एरिया पर खास ध्यान दिया गया है।
- वर्ल्ड अस्थमा डे 2026, 5 मई को GINA (ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा) की घोषित थीम के साथ मनाया जा रहा है: "अस्थमा से पीड़ित हर किसी के लिए एंटी-इंफ्लेमेटरी इनहेलर तक पहुंच - अभी भी एक ज़रूरी ज़रूरत है।" यह कैम्पेन इनहेलड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के महत्व पर ज़ोर देता है, जो सांस की नली की सूजन को कम करने, गंभीर अस्थमा अटैक को रोकने और हॉस्पिटल में भर्ती होने और मौत के खतरे को कम करने में मदद करते हैं। अस्थमा दुनिया भर में 260 मिलियन से ज़्यादा लोगों को प्रभावित करता है और हर साल लगभग 450,000 मौतों का कारण बनता है, जिनमें से कई को सही इलाज से रोका जा सकता है। आम लक्षणों में घरघराहट, सांस लेने में तकलीफ, सीने में जकड़न और लगातार खांसी शामिल हैं।
- वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2026, 7 मई को फिटनेस, स्पोर्ट्समैनशिप और हेल्दी लिविंग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जा रहा है, खासकर बच्चों और युवाओं में। सबसे पहले 1996 में अटलांटा ओलंपिक्स के सौ साल पूरे होने पर शुरू की गई इस पहल की शुरुआत प्रिमो नेबियोलो ने की थी, जो उस समय इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन (IAAF) के प्रेसिडेंट थे, जिसे अब 2019 से वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से जाना जाता है। यह दिन दौड़ने, कूदने और फेंकने जैसी एथलेटिक्स एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने को बढ़ावा देता है, जिससे युवाओं को डिजिटल ज़माने में एक्टिव रहने में मदद मिलती है। हालांकि 2026 के लिए ऑफिशियल थीम अभी तक अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन फोकस यूथ एम्पावरमेंट, इनक्लूसिविटी और फिजिकल फिटनेस पर बना हुआ है।
- भारत 7 मई, 2026 को रवींद्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती मना रहा है। गुरुदेव के नाम से मशहूर टैगोर, 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई थे। वे एक कवि, दार्शनिक, शिक्षाविद, संगीतकार और भारत के राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश के आमर सोनार बांग्ला के लेखक थे।
- टैगोर ने शांतिनिकेतन में विश्वभारती यूनिवर्सिटी शुरू की और क्रिएटिविटी, इंसानियत और नेचर पर आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया। उन्होंने कॉलोनीयल क्रूरता के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपनी ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि भी छोड़ दी। टैगोर जयंती रवींद्र संगीत, कविता पाठ, कल्चरल प्रोग्राम, सेमिनार और आर्ट परफॉर्मंस के साथ मनाई जाती है, खासकर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में।
- वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 2026, 8 मई को इंटरनेशनल रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट के मानवीय योगदान का सम्मान करने और 1828 में पैदा हुए हेनरी डुनेंट की जयंती मनाने के लिए मनाया जा रहा है। 2026 की ऑफिशियल थीम "मानवता को ज़िंदा रखना" है, जो संघर्ष, आपदाओं और हेल्थ इमरजेंसी के दौरान कमज़ोर समुदायों के लिए दया, मानवीय सेवा, ग्लोबल एकजुटता और सपोर्ट पर ज़ोर देती है। सोलफेरिनो की लड़ाई के बाद शुरू हुआ रेड क्रॉस मूवमेंट अब इंटरनेशनल कमिटी ऑफ़ द रेड क्रॉस और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जैसे संगठनों के ज़रिए 190 से ज़्यादा देशों में काम करता है। इस दिन होने वाली एक्टिविटीज़ में ब्लड डोनेशन कैम्प, हेल्थ अवेयरनेस ड्राइव, फर्स्ट-एड ट्रेनिंग और दुनिया भर में बॉलंटियर रिक्रूटिंग प्रोग्राम शामिल हैं।
- वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 2026, 8 मई को मनाया जाएगा। इसकी थीम है "अब और नहीं छिपा: जिन्हें पता नहीं चला उन्हें ढूंढना। अनदेखे को सपोर्ट करना।" यह दिन थैलेसीमिया के बारे में जागरूकता फैलाता है, जो दुनिया भर में लाखों लोगों को होने वाली एक गंभीर विरासत में मिली खून की बीमारी है। यह गंभीर दिक्कतों को कम करने के लिए जल्दी डायग्नोसिस, प्रीनेटल स्क्रीनिंग, जेनेटिक काउंसलिंग और हेल्थकेयर तक सभी की बराबर पहुंच के महत्व पर ज़ोर देता है। यह दिन बीमारी से जूझ रहे मरीजों और परिवारों को सम्मान भी देता है, साथ ही जागरूकता कैम्पेन, ब्लड डोनेशन ड्राइव और हेल्थकेयर सपोर्ट प्रोग्राम को भी बढ़ावा देता है। भारत में, 1 लाख से ज़्यादा मरीज और लगभग 40 लाख कैरियर थैलेसीमिया से प्रभावित हैं।
- वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे 2026, 8 मई को "नो वुमन लेफ्ट बिहाइंड" थीम के साथ मनाया जा रहा है। यह दुनिया भर में कैंसर की शुरुआती पहचान, जांच, इलाज और देखभाल तक सभी की बराबर पहुंच की ज़रूरत पर ज़ोर देता है। वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर कोएलिशन की अगुवाई में, यह कैम्पेन ओवेरियन कैंसर के लक्षणों जैसे पेट फूलना, पेट दर्द, पेल्विक हिस्से में तकलीफ और बार-बार पेशाब आना, के बारे में जागरूकता बढ़ाता है, जिनका पता अक्सर देर से चलता है। GLOBOCAN 2020 के अनुसार, दुनिया भर में 3.1 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए। यह पहल रिसर्च, हेल्थकेयर इंप्रोस्ट्रक्चर, जागरूकता और शुरुआती पहचान को बेहतर बनाने पर फोकस करती है, खासकर कम और मध्यम आय वाले देशों में।



**LIVE CLASSES**

# Online **LIVE** Classes for **SSC, Banking, Railways** and Other Govt Exams



**Live & Recorded  
Classes**



**PDF Notes &  
Study Material**



**Mock Tests &  
Practice Questions**



**Doubt Solving  
Sessions**

- ✓ **Expert Faculty with Interactive Classes**
- ✓ **Full Exam Syllabus Coverage + Mock Tests**
- ✓ **Courses Available in Hindi, English & Regional Languages**

**Get Started Now**

**निधन**

- टर्नर एंटरप्राइजेज के अनुसार, मशहूर मीडिया एंटरप्रेन्योर टेड टर्नर का 87 साल की उम्र में निधन हो गया है। मॉडर्न टेलीविज़न जर्नलिज़्म के पायनियर माने जाने वाले टर्नर ने 1 जून, 1980 को CNN लॉन्च करके

ग्लोबल मीडिया में क्रांति ला दी, जो दुनिया का पहला 24 घंटे का न्यूज़ चैनल था। उनके इनोवेशन ने टेलीविज़न न्यूज़ को शेड्यूल्ड बुलेटिन से बदलकर ग्लोबल इवेंट्स की लगातार लाइव कवरेज में बदल दिया। टर्नर ने टर्नर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, कार्टून नेटवर्क और टर्नर क्लासिक मूवीज़ जैसे चैनलों के ज़रिए केवल टेलीविज़न को भी नया रूप दिया।

**स्टेटिक**

पहलू	विवरण
पश्चिम बंगाल	मुख्यमंत्री: सुबेंदु अधिकारी राज्यपाल: आरएन रवि राजधानी: कोलकाता
मिजोरम	मुख्यमंत्री: पेमा खांडू राज्यपाल: सीएच विजयशंकर राजधानी: आइजोल
रूस	राष्ट्रपति: व्लादिमीर पुतिन राजधानी: मॉस्को
स्विट्ज़रलैंड	प्रेसिडेंट: गाइ पारमेलिन कैपिटल: ज्यूरिख
चीन	राष्ट्रपति: शी जिनपिंग राजधानी: बीजिंग
पुर्तगाल	राष्ट्रपति: एंटोनियो जोस सेगुरो राजधानी: लिस्बन
वियतनाम	राष्ट्रपति: टो लैम राजधानी: हनोई
गुजरात	मुख्यमंत्री: भूपेंद्र पटेल राज्यपाल: आचार्य देवव्रत राजधानी: गांधीनगर
तमिलनाडु	मुख्यमंत्री: विजय जोसेफ राज्यपाल: आर आर्लेकर राजधानी: चेन्नई
भारत का सर्वोच्च न्यायालय	CJI: जस्टिस सूर्यकांत
भारतीय रिज़र्व बैंक	राज्यपाल: संजय अग्रवाल
एनएसई	अध्यक्ष: श्रीनिवास इंजेती
सीबीएफसी	अध्यक्ष: शेखर वेम्पति
प्रसार भारती	अध्यक्ष: प्रसून जोशी

